यूरोप में वाणिज्यवाद की विशेषताएँ

डॉ. के. के. पटेल
विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
(छ.ग.)

परिचय (Introduction)

वाणिज्यवाद सरकारी हस्तक्षेप पर आधारित एक आर्थिक पद्धति या सिद्धांत था जिसका उद्देश्य राष्ट्र में आर्थिक समृद्धि लाना और राष्ट्र की शक्ति बढ़ाना था। यद्यपि इसे एक आर्थिक कार्यक्रम माना जाता है तथापि इसके उद्देश्य मुख्यतः राजनीतिक थे। मौलिक रूप से वाणिज्यवाद 16वीं और 18वीं सदी के बीच यूरोप में प्रचलित आर्थिक विचारधारा को रेखांकित करता है। वस्तुतः वाणिज्यवाद राज्य द्वारा प्रायोजित अर्थव्यवस्था है। यह एक आर्थिक प्रक्रिया है जबकि इसके उद्देश्य राजनीतिक हैं।

'वाणिज्यवाद या वाणिज्यिक पद्धति' शब्द का प्रयोग **एडम स्मिथ** ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'Wealth of Notion' में किया है। इस पुस्तक में पहली बार उस समय तक जारी आर्थिक सिद्धांत के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना भी की है। फिर भी वाणिज्यवाद को एक सुव्यवस्थित विचारधारा मानना भ्रामक होगा क्योंकि देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार इसके वैचारिक आयाम और क्रियान्वयन बदलते रहे हैं। इसके अधिकतर प्रतिपादकों ने विशिष्ट क्षेत्र के आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र के संगठनों के परिप्रेक्ष्य में इस विचारधारा को लागू किया। दूसरी ओर इस कारण से भी यह एकीकृत वैचारिक पद्धति नहीं मानी जा सकती क्योंकि वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग पहली तब हुआ जब इस विचारधारा को असामयिक व अप्रासांगिक मान कर इसके अलोचक इसे अस्वीकृत कर रहे

थे। इन विचारकों में एडम स्मिथ अग्रणी थे।

वाणिज्यवादी आर्थिक समृद्धि एवं राज्य की शक्ति में वृद्धि के लिए एक प्रकार का राजकीय हस्तक्षेप था और यह प्रक्रिया 1600–1750 के बीच अपने चरम पर थी जबकि इसका आरंभिक रूप 13वीं सदी के मध्य में ही उभर कर आता है। वाणिज्यवाद की आरंभिक प्रेरणा पवित्र रोमन साम्राज्य के राज्यों के आर्थिक पुनर्निर्माण की समस्या के साथ आयी क्योंकि 30 वर्षीय युद्ध (1618–48) के परिणामस्वरूप इन राज्यों की अर्थव्यवस्था अस्त–व्यस्त हो गयी थी। वाणिज्यवाद एक आर्थिक कारण था परंतु इसका उद्देश्य राजनीतिक था इसलिए इसे Statism भी कहा जाता है।

वाणिज्यवाद की विशेषताएं (Features of Mercantilism)

वाणिज्यवाद का अध्ययन करने पर हम उसमें अनेक विशेषताओं को पाते हैं। यद्यपि देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार उसके स्वरूप में परिवर्तन स्वभाविक है परंतु फिर भी हम कुछ आधारभूत विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं :

1. यह व्यापार वाणिज्य पर राज्य के एकाधिकार, राज्य के नियंत्रण तथा राज्य द्वारा इसके विनिमय पर बल देता है।

2. व्यक्ति और समाज की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का राज्य को पूरा अधिकार दिया जाता है।

3. वाणिज्यवाद के अन्तर्गत वाणिज्य और व्यापार में अधिकतम भागीदारी निभाकर अधिकतम मुनाफा कमाने का प्रयास किया जाता है।

4. वाणिज्यवाद का उद्देश्य अधिकतम बुलियन का संग्रह करना है क्योंकि इस समय लोगों का मानना था कि जिस राष्ट्र के पास जितनी अधिक बुलियन होगी उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही सक्षम व मजबूत होगी ।

5. वाणिज्यवाद में संयुक्त पूंजी उद्यम का गठन किया जाता है ताकि अधिकतम पूंजी के द्वारा व्यापार के अधिकतम हिस्से पर नियंत्रण किया जा सके।

6. वाणिज्यवाद में चार्टर कम्पनियों का विकास होता है। वस्तुतः संयुक्त पूंजी उद्यम वाली फर्मे किसी क्षेत्र विशेष का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश करती हैं और इस क्रम में संबंधित देशों के शासक इन कम्पनियों को चार्टर प्रदान कर व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करते हैं। इसलिए ये कम्पनियां चार्टर कम्पनियां भी कहलाती है। British East India Company (1600), Dutch East India Company (1602) तथा French East India Company (1664) इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

7. वाणिज्यवाद में निर्यात को अधिकतम व आयात को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है ताकि व्यापार संतुलन संबंधित देश के पक्ष में बना रहे।

8. विदेशी वस्तुओं के आयात को निर्यात करने के लिए उच्च चुंगी दर लगायी जाती है। ताकि आयात को हतोत्साहित किया जा सके।

9. वाणिज्यवाद में यह माना जाता है कि विश्व व्यापार का परिणाम मात्र निश्चित होता है और सभी देशों का यह प्रयास होना चाहिए कि उसमें अधिकतम हिस्सा प्राप्त करे।

10. अधिकतम मुनाफा, बुलियन का संग्रह और व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए विश्व व्यापार में अधिकतम हिस्सेदारी जरूरी है और इस जरूरत को पूरा करता है। उपनिवेश दूसरे शब्दों में, उपनिवेशवादी भावना का विकास वाणिज्यवाद के अंदर ही हुआ वस्तुतः वाणिज्यवादी नीतियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय राज्यों के द्वारा किया गया, जिसमें एक ओर सामंतवादी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन लाया तो वहीं दूसरी ओर चर्च की मान्यताओं को भी चुनौती दी। भौगोलिक खोजों की प्रक्रिया ने जहां बंद विश्व की अवधारणा को खंडित कर दिया वहीं दूसरी ओर व्यापार और वाणिज्य के अन्तर्राष्ट्रीय प्रसार को प्रोत्साहित किया। व्यापारिक विस्तार में राज्य की सक्रिय भागीदारी एवं संयुक्त पूंजी उद्यम तथा चार्टर कम्पनियों के विकास में राज्य के व्यापारिक व वाणिज्यिक वर्ग को एक–दूसरे के निकट ला दिया। इनके परिणामस्वरूप उपनिवेशवादी का क्रियान्वयन राज्य के द्वारा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था के स्वरूप में गुणात्मक व परिणात्मक दोनों परिवर्तन आये।

विभिन्न देशों में वाणिज्यवाद के क्रियान्वयन में विविधता देखने को मिलती है। विविधता

की सर्वप्रमुख वजह यह थी कि विभिन्न देशों की परिस्थितियां अलग–अलग थीं। दूसरी प्रमुख वजह यह थी कि, विभिन्न देशों के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक ढांचे में अंतर था। तीसरी प्रमुख वजह यह थी कि विभिन्न यूरोपीय देशों की जनता के मानसिकता में भी अंतर था इसलिए एक ही सिद्धांत को उन्होंने अलग–अलग रूपों में स्वीकार किया। चौथी प्रमुख वजह यह थी कि विभिन्न देशों के द्वारा इसके क्रियान्वयन में भी अंतर था। कुछ देश इसके लिए सैन्य कार्यवाही में भी तत्पर थे वहीं दूसरे राज्य इससे परहेज करते थे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि देश, काल व परिस्थितियों के अनुसार इसके क्रियान्वनयन में विविधता देखने को मिलती है।

फ्रांस में वाणिज्यवादी नीतियों का क्रियान्वयन मूल रूप से तत्कालीन विदेश मंत्री कोल्बर्ट के द्वारा किया गया। कोल्बर्ट से संबंधित इन नीतियों की दो विशेषताएं थीं। इनमें से एक विशेषता जहां ब्रिटिश नीति से समानता रखती थी वहीं दूसरी व्यवस्था विदेश नीति से बिल्कुल अलग थी। कोल्बर्ट भी ब्रिटिश वाणिज्यवादियों की तरह अनुकुल व्यापर संतुलन, बुलियन के संग्रह एवं अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध बल प्रयोग पर जोड़ देता था। दूसरी ओर ब्रिटिश वाणिज्यवादियों के विपरीत कोल्बर्ट ने हस्तक्षेप पर आधरित व्यापारिक गतिविधियों पर बल दिया ताकि कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी आर्थिक संशाधनों का संग्रह किया जा सके। साथ ही उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारा जा सके जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी मांग बढ़े। इसके अतिरिक्त कोल्बर्ट शारीरिक रूप से सक्षम गरीबों को रोजगार देना चाहता था ताकि सामाजिक तनाव पर भी नियंत्रण लाया जा सके।

वाणिज्यवाद का पतन (Decline of Mercantilism)

पूंजीवाद का वाणिज्यवादी चरण मौटे तौर पर 1250–1750 ई. के मध्य माना जाता है जिसका परिपक्व चरण 1500–1750 के बीच माना जाता है। अपनी तमाम विशेषताओं के बावजूद धीरे–धीरे वाणिज्यवादी नीतियां अप्रसांगिक होती चली गयी। ऐसा मुख्य रूप से आर्थिक नीतियों में आये परिवर्तन व वाणिज्यवाद में अन्तर्निहित के कारण हुआ। यघपि अलग–अलग देशों में इसके पतन के कारण अलग–अलग बताये जा सकते है तथापि कुछ

सामान्य कारणों को रेखांकित किया जा सकता है। ये कारण निम्नलिखित है–पतन के कारण

1. बड़े–बड़े वाणिज्यिक बैंकों के उदय के कारण विभिन्न रूपों में शाख का उपयोग किया जाने लगा जिससे बुलियन का महत्व कम हो गया।

2. ऊंची चुंगी दर के कारण विश्व व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो गया जिसे तोड़ने के लिए ऊंची चुंगी दर को हटाना अनिवार्य हो गया।

3. आरंभिक दौर में जहां आयात की तुलना में निर्यात अधिक रखने का अर्थव्यवस्था पर

सकारात्मक प्रभाव पड़ा वहीं बाद में जब सभी देशों ने ऐसे ही प्रयास किये तो विश्व व्यापार मे गतिरोध उत्पन्न हो गया और इस गतिरोध को तोड़ने के लिए निर्यात अधिकता को वापस लेना अनिवार्य था।

4. बाद के अर्थशास्त्रियों ने इस बात को तार्किक तरीके से सिद्ध किया कि विश्व व्यापार की अधिकतम मात्रा या कुल मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।

5. बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध कराने और फिर उस पूंजी को नियंत्रित करने के लिए बड़े–बड़े बैंकों की स्थापना की गयी। Bank of Sweden, वं Bank of England इसके प्रमुख उदाहरण है।

6. औद्योगिक क्रांति ने वाणिज्यिवाद को अप्रासंगिक बना दिया क्योंकि पूंजीवाद के इस चरण में औद्योगिक पूंजीपतियों के लिए व्यापारिक एकाधिकार नहीं बल्कि मुक्त व्यापार अधिक लाभप्रद था।

निष्कर्ष (Conclusion)

वाणिज्यिक क्रांति और फिर बाद में होने वाले औद्योगिक क्रांति ने धीरे–धीरे उदयीमान बुर्जुआ वर्ग को इतना सक्षम बना दिया कि अब उसकी निर्भरता राज्य पर अधिक नहीं रही और वे राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप की वकालत करने लगे जिससे वाणिज्यवाद अलोकप्रिय होने लगा व मुक्त व्यापार को लोकप्रियता मिली।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम देखते है कि वाणिज्यवाद पूंजीवाद की एक विशेष स्थिति है जो राज्य द्वारा प्रयोजित अर्थव्यवस्था की बात करता है। निर्यात अधिशेष, अधिकतम बुलियन का संग्रह व उपनिवेशवाद इसकी मूलभूत विशेषताएं है। यह आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप व उसकी प्रभावी भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। अपनी तमाम विशेषताएं के वावजूद समय के साथ यह विचारधारा अलोकप्रिय होने लगी क्योंकि औद्योगिक पूंजीवादी चरण में व्यापारिक एकाधिकार की जगह मुक्त व्यापार लोकप्रिय होने लगा।